



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938

No. 213]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

सा.का.नि. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध दिनांक 1 मार्च, 2017 से एस्टोनिया पर लागू होंगे और भारत गणतन्त्र की सरकार और एस्टोनिया गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को किए गए करार का सम्पूर्ण पाठ निम्नवत अधिसूचित करती है। करार अनुसमर्थन की लिखत पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 07.12.2016 को और एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27.02.2017 को हस्ताक्षर किए गए।

दण्डादेशित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार

और

एस्टोनिया गणराज्य की सरकार

के बीच करार

इसके उपरान्त भारत गणराज्य की सरकार और एस्टोनिया गणराज्य की सरकार को संविदाकारी देश कहा जाएगा;

दण्डादेशित व्यक्तियों के अपने-अपने देश में सामाजिक पुनर्वास को सुलभ बनाने की वांछा करते हुए; और

यह विचार करते हुए कि विदेशी राष्ट्रियों, जिन्हें कोई अपराध कारित करने के परिणामस्वरूप अभियोजित किया गया है और सजा प्रदान की गई है, को उनके अपने समाज में सजा काटने का अवसर देकर यह उद्देश्य पूरा किया जाना चाहिए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:-

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

करार के प्रयोजन के लिए:

(क) "अधिनिर्णय" का अर्थ है कि न्यायालय या न्याधिकरण का निर्णय या आदेश जो सजा देता है;

(ख) "दण्डालदेशित देश" का अर्थ वह देश जिसमें दण्डादेशित व्यक्ति को सजा काटने के लिए या बाकी बची सजा काटने के लिए स्थानांतरित किया जा सके या स्थानांतरित किया गया है;

- (ग) "सजा" का अर्थ है ऐसी सजा या उपाय जिसमें निर्धारित अवधि के लिए आपराधिक न्यायाधिकार के प्रयोग हेतु आजीवन कारावास हेतु न्यायालय या अधिकरण द्वारा आदेशित स्वतंत्रता से वंचित रखना शामिल हो;
- (घ) "दण्डालदेशित व्यक्ति" का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो आपराधिक न्यायालय जिसमें संधिकर्ता देशों में लागू कानून के अंतर्गत तत्समय गठित न्यायालय शामिल हैं, द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के अंतर्गत कारावास की सजा काट रहा हो;
- (ङ.) "अन्तरणकर्ता देश" का अर्थ है वह देश जिसमें उस व्यक्ति को सजा दी गई थी, जिसे अन्तरित किया जा सकता है या किया गया है।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धान्त

1. संविदाकारी देश के क्षेत्र में दण्डालदेशित व्यक्ति को इस करार के प्रावधानों के अनुसार उसे मिली सजा काटने के लिए अन्य संविदाकारी देश के क्षेत्र में अन्तरित किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ, वह अन्तरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश को इस करार के अंतर्गत अन्तरित होने के लिए अपनी इच्छा के बारे में बता सकता है।
2. किसी भी दण्डालदेशित व्यक्ति द्वारा अन्तरण के लिए अनुरोध किया जा सकता है, जो संविदाकारी देश का राष्ट्रिक हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जा सकता है जो संविदाकारी देश को आवेदन प्रस्तुत करके संविदाकारी देश के कानून के अनुसार उनकी ओर से कार्य करने का हकदार हो और इस भांति जो संविदाकारी देश की सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो।

अनुच्छेद 3

केन्द्रीय प्राधिकरण

1. संविदाकारी देशों की ओर से इस करार के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी प्राधिकरण निम्नानुसार है:
 - (क) भारत गणराज्य की ओर से : गृह मंत्रालय
 - (ख) एस्टोनिया गणराज्य की ओर से : न्याय मंत्रालय
2. यदि संविदाकारी देशों में से कोई अपने सक्षम प्राधिकारियों को बदलता है, वह अन्य देश को इस बारे में राजनयिक चैनलों के माध्यम से अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 4

अन्तरण के लिए शर्तें

1. दण्डालदेशित व्यक्ति को इस करार के अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियों में अन्तरित किया जा सकता है:
 - (क) व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक है;
 - (ख) दण्डालदेशित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नहीं दिया गया है;
 - (ग) अधिनिर्णय अंतिम है;
 - (घ) अन्तरित करने वाले देश में दण्डालदेशित व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाहियां लम्बित नहीं हैं जिसमें उसकी, उपस्थिति अपेक्षित है;
 - (ङ.) दण्डालदेशित व्यक्ति को मिलिटरी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है;
 - (च) अन्तरण के लिए किसी अनुरोध की प्राप्ति के समय दण्डालदेशित व्यक्ति को न्यूनतम छः माह की सजा काटना बाकी है या वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है;
 - (छ) वह कृत्य या अपराध जिनके लिए उस व्यक्ति को अन्तरण देश में सजा प्रदान की गई थी, वे हैं जो प्राप्तकर्ता देश में अपराध के रूप में दण्डनीय है, या दाण्डिक अपराध कहलाते हैं यदि ये उनके क्षेत्र में कारित किए जाते हैं;
 - (ज) दण्डालदेशित व्यक्ति की अभिरक्षा प्राप्तकर्ता देश में अंतरित करना अन्तरणकर्ता देश की प्रभुता, सुरक्षा या किसी अन्य आवश्यक हित के विरुद्ध नहीं होगी;
 - (झ) दण्डालदेशित व्यक्ति द्वारा अन्तरण के लिए सहमति दी जाती है या उसकी आयु या भौतिक या मानसिक स्थिति के मद्देनजर कोई संविदाकारी देश यह आवश्यक समझता है कि संविदाकारी देश के कानून के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से कार्य करने का हकदार होगा; और
 - (ञ) अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अन्तरण के लिए सहमत हो।
2. अपवादिक मामलों में, अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश दण्डालदेशित व्यक्ति द्वारा शेष भुगते जाने वाली अवधि छह महीनों से कम होने पर भी अन्तरण हेतु सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 5**सूचना प्रदान करने संबंधी दायित्व**

1. यदि दण्डादेशित व्यक्ति ने अन्तरणकर्ता देश से इस करार के अन्तर्गत अन्तरित होने की रूचि अभिव्यक्त की है, तब अन्तरणकर्ता देश, जब तक यदि प्राप्तकर्ता और अन्तरणकर्ता देश में से कोई भी देश यह पहले ही निर्णय नहीं कर चुका है कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं होगा, प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा:

- (क) प्राप्तकर्ता देश में दण्डादेशित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म की तारीख और स्थान और पता, यदि कोई हो, साथ ही उसके पासपोर्ट अथवा किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज की एक प्रति, और यथासम्भव दण्डादेशित व्यक्ति की उंगलियों के निशान भी भेजेगा।
- (ख) उन तथ्यों की विवरणी जिन पर सजा देना आधारित था;
- (ग) सजा की प्रकृति, अवधि और आरम्भ होने की दिनांक;
- (घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति और कानून के उस संगत प्रावधान की एक प्रति जिसके अन्तर्गत दण्डादेशित व्यक्ति को सजा प्रदान की गई है।
- (ङ.) जहां भी आवेदन का निपटान करना और कारावास की प्रकृति के बारे में निर्णय करना संगत हो, दण्डादेशित व्यक्ति के पूर्ववृत्त और चरित्र के बारे में चिकित्सा, सामाजिक या अन्य कोई प्रतिवेदन;
- (च) कोई अन्य सूचना जिसे प्राप्तकर्ता देश, उसे अन्तरण की संभावना पर विचार करने के लिए अधिकार देने और उसे उसके कानून के अधीन दण्डादेशित व्यक्ति को अन्तरण के पूरे परिणामों के बारे में सूचित करने का अधिकार देने के लिए, आवश्यक होना विनिर्दिष्ट करे।
- (छ) अन्तरित किए जाने वाले दण्डादेशित व्यक्ति का अनुरोध अथवा अन्तरणकर्ता देश की विधि के अनुसार उसकी तरफ से कार्रवाई करने के लिए हकदार व्यक्ति का अनुरोध;
- (ज) विवरणी जिसमें कि विचारण-पूर्व कैद, माफी, दण्ड के प्रवर्तन के संगत कोई अन्य तथ्य सहित कितनी सज़ा पहले ही काटी जा चुकी है, को दर्शाया गया हो; तथा
- (झ) दण्डादेशित व्यक्ति के अन्तरण पर सहमति संबंधी अन्तरणकर्ता देश से एक विवरणी।

2. इस करार के अन्तर्गत अनुरोध के बारे में कोई निर्णय लेने का अधिकार देने के उद्देश्य से, प्राप्तकर्ता देश, जब तक यदि प्राप्तकर्ता और अन्तरणकर्ता देश में कोई भी देश यह पहले ही निर्णय नहीं कर चुका है कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं होगा, अन्तरणकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज भेजेगा:

- (क) विवरणी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दण्डादेशित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक राष्ट्रिक है।
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान है कि वह क्रियाकलाप अथवा अनाचरण जिसके कारण अन्तरणकर्ता देश में दण्ड आरोपित किया गया है, जो प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध गठित करता है, अथवा उसके भू-भाग में कारित किए जाने पर दण्डनीय अपराध माना जाएगा;
- (ग) यदि लागू हो तो दण्डादेशित व्यक्ति संबंधी इस करार के अनुच्छेद 9 के पैरा 2 के प्रभाव संबंधी विवरणी सहित दण्डादेशित व्यक्ति के अन्तरण के पश्चात् प्राप्तकर्ता देश में सजा की अवधि और इसके प्रवर्तन के संबंध में किसी कानून या विनियम के प्रभाव की विवरणी;
- (घ) दण्डादेशित व्यक्ति के अन्तरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सम्मति और दण्डादेशित व्यक्ति की बाकी बची सजा पूरी कराने के लिए एक वचनपत्र; तथा
- (ङ.) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जिसे अन्तरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 6**अनुरोध और उत्तर**

1. अन्तरण हेतु अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो, लिखित में किए जाएंगे और अन्तरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राजनयिक माध्यमों से प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित किए जाएंगे। उत्तर भी उन्हीं माध्यमों से भेजे जाएंगे।

2. प्राप्तकर्ता देश अपने इस निर्णय के बारे में कि अनुरोध के अन्तरण से सहमत हुआ जाए या नहीं, अन्तरणकर्ता देश को शीघ्रता से सूचित करेगा।

अनुच्छेद 7**सम्मति और इसका सत्यापन**

1. अन्तरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1(i) के अनुसार अन्तरण की अपेक्षित सम्मति देने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा स्वेच्छा से और उसके विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। ऐसी सम्मति देने के लिए प्रक्रिया अन्तरणकर्ता देश कानून द्वारा शासित होगी।
2. अन्तरणकर्ता देश, यह सत्यापित करने के लिए कि ऐसी सम्मति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है, प्राप्तकर्ता देश को एक अवसर प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 8**प्राप्तकर्ता देश पर अन्तरण का प्रभाव**

1. प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन, उसके राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यथा अपेक्षित न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सजा का प्रवर्तन जारी रखेंगे।
2. इस करार के अनुच्छेद 11 के उपबंधों के शर्ताधीन, सजा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगा और केवल वही देश सभी समुचित निर्णय लेने में सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9**सजा का लगातार प्रवर्तन**

1. प्राप्तकर्ता देश, अन्तरणकर्ता देश द्वारा यथानिर्धारित सजा की विधिक प्रवृत्ति और अवधि के लिए बाध्य होगा।
2. सजा यदि इसकी प्रकृति और अवधि, अथवा दोनों, के हिसाब से प्राप्तकर्ता देश के कानून के संगत नहीं है, तो वह देश, अन्तरणकर्ता देश की पूर्व सम्मति से न्यायालय के या प्रशासनिक आदेश द्वारा उसी प्रकार के अपराध हेतु उसके स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित सजा के अनुसार सजा को रूपान्तरित कर सकता है। सजा की प्रकृति और अवधि से संबंधित रूपान्तरित सजा, जहां तक संभव हो, अन्तरणकर्ता देश के निर्णय द्वारा आरोपित सजा के समान होगी।

अनुच्छेद 10**अन्तरणकर्ता देश पर सजा पूरी करने का प्रभाव**

प्राप्तकर्ता देश जब इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1(क) के अन्तर्गत अन्तरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि सजा पूरी हो गई है, तब ऐसी अधिसूचना अन्तरणकर्ता देश में सजा पूरी करने के प्रभाव के रूप में मानी जाएगी।

अनुच्छेद 11**निर्णय और क्षमादान, राजक्षमा, तथा लघूकरण की पुनरीक्षा**

1. केवल अन्तरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा हेतु किसी आवेदन के बारे में निर्णय करेगा।
2. संविदाकारी देशों में से कोई भी देश अपने संविधान और अन्य कानूनों के अनुसार क्षमादान, राजक्षमा अथवा सजा का लघूकरण कर सकता है।

अनुच्छेद 12**सजा प्रवर्तन का समापन**

1. अन्तरणकर्ता देश उसके भू-भाग पर लिए गए उन किन्हीं भी निर्णयों के बारे में जिनसे सजा अथवा सजा के किसी भाग के प्रवर्तन का समापन होता हो, अवलिम्ब प्राप्तकर्ता देश को अधिसूचित करेगा।
2. अन्तरणकर्ता देश द्वारा किसी निर्णय अथवा ऐसे किसी, उपाय जिसके परिणामस्वरूप सजा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, के बारे में जैसे ही सूचित किया जाता है, प्राप्तकर्ता देश सजा अथवा इसके किसी हिस्से के प्रवर्तन का समापन कर देगा।

अनुच्छेद 13**सजा प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश अन्तरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा:
 - (क) जब सजा प्रवर्तन पूरा किया जा चुका है; अथवा
 - (ख) यदि दण्डादेशित व्यक्ति सजा प्रवर्तन पूरा हो जाने से पहले ही हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश उसकी शेष सजा पूरी कराने के प्रयोजनों हेतु उसे हिरासत में लिए जाने तथा प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत अपराध कारित करने हेतु उसे उत्तरदायी घोषित करने हेतु उपाय करेगा।
2. यदि अन्तरणकर्ता देश ऐसी अपेक्षा करता है तो प्राप्तकर्ता देश सजा के प्रवर्तन के संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

अनुच्छेद 14**पारगमन**

1. यदि कोई भी संविदाकारी देश किसी अन्य तीसरे देश के साथ दण्डादेशित व्यक्तियों के अन्तरण हेतु समझौते करता है, तो दूसरा संविदाकारी देश ऐसे समझौतों के अनुसरण में अन्तरित किए जा रहे दण्डादेशित व्यक्तियों का अपने भू-भाग से पारगमन सुलभ करने हेतु सहयोग करेगा, यह देश पारगमन से केवल तब इंकार कर सकता है;

(क) यदि दण्डादेशित व्यक्ति उनके स्वयं के राष्ट्रियों में से एक है।

(ख) यदि अनुरोध से संविदाकारी देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा अन्य किसी आवश्यक हित का अतिक्रमण होता है।

2. ऐसा अन्तरण चाहने वाला संविदाकारी देश ऐसे पारगमन के बारे में दूसरे संविदाकारी देश को अग्रिम सूचना देगा।

अनुच्छेद 15**लागत**

इस करार की प्रयुक्ति पर की जाने वाली लागतों का वहन प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जाएगा सिवाय उन लागतों के जो केवल अन्तरणकर्ता देश के भू-भाग में होती हैं। तथापि, प्राप्तकर्ता देश दण्डादेशित व्यक्ति अथवा किसी स्रोत से अन्तरण की पूरी लागतों अथवा इसके हिस्सों की मांग अथवा वसूली के लिए कह सकता है।

अनुच्छेद 16**भाषा**

अनुरोध और समर्थक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न किया जाएगा।

अनुच्छेद 17**प्रयुक्ति का क्षेत्र**

यह करार, इस करार के लागू होने से पहले अथवा इसके पश्चात् प्रदान किए गए दंडादेशों के प्रवर्तन के संबंध में लागू होगा।

अनुच्छेद 18**विवादों का निपटारा**

1. केन्द्रीय प्राधिकरण, इस करार के निर्वचन, लागू होने अथवा इसके कार्यान्वयन से व्युत्पन्न किसी विवाद को पारस्परिक रूप से निपटाने का प्रयास करेंगे।

2. यदि केन्द्रीय प्राधिकरण किसी विवाद को आपस में नहीं सुलझा पाते हैं तो इसे राजनयिक माध्यमों से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 19**दण्डादेशित व्यक्तियों की सुपुर्दगी**

अन्तरणकर्ता देश द्वारा अन्तरित व्यक्ति की प्राप्तकर्ता देश को सुपुर्दगी, अन्तरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश के मध्य मतैक्य वाले स्थान पर की जाएगी। प्राप्तकर्ता देश, बंदी के अन्तरणकर्ता देश से अभिगमन हेतु उत्तरदायी होगा और अन्तरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दण्डादेशित व्यक्ति की हिरासत के लिए भी उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 20**संशोधन**

संविदाकारी देशों द्वारा इस करार में किसी संशोधन अथवा आशोधन पर बनी सहमति इस करार के प्रवृत्त होने के तरीके से ही प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 21**अन्तिम उपबंध**

1. प्रत्येक संविदाकारी देश, इस करार के प्रवृत्त होने के लिए अपेक्षित अपनी आवश्यक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लेने के पश्चात् राजनयिक माध्यमों से यथासम्भव शीघ्र लिखित में दूसरे संविदाकारी देश को सूचित करेगा। यह करार अन्तिम अधिसूचना की तारीख के दूसरे माह के पहले दिन से लागू होगा।

2. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा। तथापि, कोई भी संविदाकारी देश इस करार को, दूसरे देश को इस करार को समाप्त करने का लिखित नोटिस देकर समाप्त कर सकता है। यह समापन ऐसे नोटिस की तारीख से छह माह के बाद प्रभावी होगा।
3. समापन के बावजूद यह करार उन बंदियों की सजा के प्रवर्तन पर लागू होना जारी रहेगा जिन्हें इस करार के अधीन इस करार के समाप्त होने की तारीख से पहले अन्तरित किया गया है।

इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होने पर, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वर्ष 2016 के नवम्बर माह की 15 तारीख को नई दिल्ली में हिन्दी, एस्टोनियन और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियां में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित है। तथापि, निर्वचन की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

एस्टोनिया गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह./-
(दिलीप कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

ह./-
(रिहो कुव)
एस्टोनिया गणराज्य के राजदूत

[फा. सं. वी -17011/8/2015-पीआर]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2017

G.S.R. 270(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to Estonia with effect from the 1st day of March, 2017 and notifies the full text of the agreement entered into between the Government of the Republic of India and the Government of Estonia on the 15th day of November, 2016 as follows. Instrument of the Ratification of the Agreement was signed by the President of India on 07-12-2016 and by the Republic of Estonia on 27-02-2017.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of criminal offences, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) "Receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;

- (d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) “Transferring State” means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

ARTICLE 2

General Principles

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring State or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State

ARTICLE 3

Central Authorities

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
 - a) For the Republic of India: Ministry of Home Affairs
 - b) For the Republic of Estonia: Ministry of Justice.
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through diplomatic channels.

ARTICLE 4

Conditions for transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the Receiving State;
 - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
 - (c) the judgment is final;
 - (d) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required;
 - (e) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
 - (f) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
 - (g) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the Transferring State are those which are punishable as a crime in the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
 - (h) transfer of custody of the sentenced person to the Receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the Transferring State;
 - (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
 - (j) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.
2. In exceptional cases, the Transferring and Receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

ARTICLE 5**Obligation to furnish information**

1. If the sentenced person has expressed an interest to the Transferring State in being transferred under this Agreement, the Transferring State shall send the following information and documents to the Receiving State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the Receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and fingerprints of the Sentenced Person, as possible;
- (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (e) a medical, social or any other report regarding the antecedents and character of the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (f) any other information which the Receiving State may specify as required, to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Transferring State;
- (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence; and
- (i) A statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) A statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;
- (b) A copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) A statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) The willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) Any other information or document which the Transferring State may consider necessary.

ARTICLE 6**Requests and replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed by the Central Authority of the Transferring State through diplomatic channels to the Central Authority of the Receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.

2. The Receiving State shall promptly inform the Transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

ARTICLE 7**Consent and its verification**

1. The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.

2. The Transferring State shall afford an opportunity to the Receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 8**Effect of transfer for the Receiving State**

1. The competent authorities of the Receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

ARTICLE 9**Continued enforcement of sentence**

1. The Receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.

ARTICLE 10**Effect of completion of sentence for the Transferring State**

When the Receiving State notifies the Transferring state under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging the sentence in the Transferring state.

ARTICLE 11**Review of judgment and Pardon, amnesty or commutation**

1. The Transferring State alone shall decide on any application for review of the judgment.
2. Either of the contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its constitution or other laws.

ARTICLE 12**Termination of enforcement of sentence**

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.
2. The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 13**Information on enforcement of sentence**

1. The Receiving State shall notify the Transferring State:
 - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
 - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/ her liable for committing an offence under the relevant law of the Receiving State.
2. The Receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the Transferring State.

ARTICLE 14**Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit

- (a) if the sentenced person is one of its own nationals.
- (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.

2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

ARTICLE 15

Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring State. The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

ARTICLE 16

Language

Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.

ARTICLE 17

Scope of Application

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 18

Settlement of Disputes

- (1) The Central Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
- (2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

ARTICLE 19

Handing Over of Sentenced Persons

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving State. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the Transferring State.

ARTICLE 20

Amendments

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

ARTICLE 21

Final Provisions

1. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its necessary legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.
2. The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the Contracting State by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on the 15th day of November 2016, in two originals, each in the, Hindi, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

Sd/-

(Dilip Kumar)

Joint Secretary to the Govt. of India

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ESTONIA**

Sd/-

(Riho Kruuv)

Ambassador of the Republic of Estonia

[F. No. V-17011/8/2015-PR]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.